राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

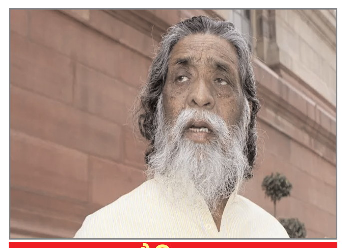

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 23 अप्रैल 2026
वर्ष 14,अंक 14, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

लोकतंत्र की सशक्त सारथी बनेंगी महिलाएंः रमेश वाजपेयी...03

खोल दो नहीं तो...हॉर्मुज में चीन की एंट्री, ईरान को दिया सख्त आदेश!...04

गहरी साजिश थी नोएडा का उपद्रव, 10 हजार में छह राउंड गोली पुलिस को मिले इनपुट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नोएडा। 10 हजार में छह राउंड गोली चलानी है, कहां भेजना है, आदि के ऑडियो और चौंकाने वाले मैसेज पुलिस को मिले हैं। इससे पता चलता है कि वेतन वृद्धि आंदोलन की आड़ में 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा फैलाकर यहां औद्योगिक उत्पादन ठप करने की गहरी साजिश थी। दरअसल, जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा में कुछ समय से बड़े पैमाने पर औद्योगिक पूंजी निवेश हुआ है। बहुराष्ट्रीय इकाइयां स्थापित हुई हैं, उससे गौतमबुद्ध नगर ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश विकास के मॉडल के रूप में अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभरा है।

सीटू ने भी दी थी बड़े आंदोलन की चेतावनी

सूत्रों का दावा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विरोध प्रदर्शन के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश थी, ताकि यहां पूंजी निवेश को प्रभावित कर सकें। इसलिए उपद्रव की साजिश रची गई। जांच में यह भी बात सामने आई है कि एक अप्रैल को एक अन्य संगठन सीटू ने भी काला दिवस मानकर चेतावनी दी थी कि 15 दिन में नोएडा में बड़ा आंदोलन होगा। इससे लगता है कि उपद्रव की पटकथा नियोजित तरीके से पूर्व में लिखी जा चुकी थी।

इसमें शामिल लोगों को पुलिस चिह्नित करने और पकड़ने में जुटी है। उधर, पुलिस रूपेश राय, सृष्टि, मनीषा और आकृति को रिमांड पर लेकर हिंसा के बारे में जानकारी कर रही। कुछ अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं। यह भी पता चला है कि मजदूर बिगुल संगठन श्रमिकों को भड़काने के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल व वेबसाइट का भी दुरुपयोग करता था। इसके जरिए श्रमिकों को भड़काने का काम किया जाता था।

1996 में शुरू किया था मजदूर बिगल अखबार

संगठन ने 1996 में मजदूर बिगल अखबार भी शुरू किया था। कई ऐसे लोगों के आलेख भी ऑनलाइन पोस्ट कर रखे हैं, जिनमें मजदूरों के दमन की बात लिखी है। तीन हजार रुपये में संगठन की आजीवन सदस्यता देते थे। इसका संचालन लखनऊ से होता है, लेकिन पूरे देश में इसके नेटवर्क की जड़े फैली हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र व हरियाणा में नेटवर्क है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस जांच के लिए संगठन के लखनऊ स्थित डी -68 निराला नगर पहुंची तो वहां कोई और रहता मिला। गलत पता मिलने को भी पुलिस साजिश का हिस्सा मानकर चल रही है।

बिगुल संगठन के पीछे किसी राजनीति पार्टी का हाथ तो नहीं, हो रही है जांच

बिगुल संगठन लखनऊ से संचालित हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ें देश के कई हिस्सों में फैली हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है।

ऐसी आशंका है कि विधान सभा चुनाव से पहले मजदूर और श्रमिकों को भड़काने की बड़े पैमाने पर योजना तो नहीं बनी थी। क्योंकि कोई संगठन बिना राजनीतिक सपोर्ट लिए अचानक इतना बड़ा आंदोलन कर भीड़ एकत्र नहीं कर सकता। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि संगठन को किस राजनीतिक दल का अंदरखाने समर्थन प्राप्त है।

पाकिस्तानी हैंडलर्स दिखा रहे थे गलत खबर

घटना के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा 20 मौत व 99 घायल होने की पोस्ट की गई। यह उपद्रव को और चिंगारी देने की गहरी साजिश का हिस्सा लग रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपित का नगेटिव खबर चलाने लिए किस-किस से संपर्क है।

सात अप्रैल को भी आरोपित गया था जेल

आरोपित रूपेश राय एकता संघर्ष समिति भी चलाता था। सात अप्रैल को कुलेसरा गांव में बिजली कनेक्शन संबंधी समस्या पर भाषण के जरिए लोगों को भड़काया था। तब पुलिस ने शांतिभंग करने की धारा 151 में जेल भेजा था।

चित्रकूट में जंगल की आग से बाघ गणना प्रभावित, कैमरा ट्रैप जले; 20 दिन में आठ बार अगलगी से बिगड़ा संतुलन

चित्रकूट। रानीपुर टाइगर रिजर्व में चल रही अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 पर जंगल की आग का असर साफ दिख रहा। पिछले 20 दिन में आठ बार जंगल में लगी आग के कारण वन्यजीवों की गतिविधियां प्रभावित हैं, जबकि गणना में उपयोग किए जा रहे पांच कैमरा ट्रैप भी जलकर नष्ट हो गए हैं। ट्रैप कैमरा एक विशेष डिजिटल कैमरा है, जो मोशन सेंसर (गति संवेदक) या इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग करके बिना किसी इंसान की उपस्थिति के जंगली जानवरों की तस्वीरें या वीडियो स्वचालित रूप से रिकार्ड करता है। इनका उपयोग वन्यजीवों की निगरानी, संरक्षण व उनपर शोध के लिए उपयोग किया जाता है। एक कैमरा ट्रैप की कीमत लगभग 48 हजार रुपये है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वन्यजीव विशेषज्ञ एस डबोलकर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम गणना कर रही है। टीम मारकुंडी प्रथम व द्वितीय रेंज के घने जंगलों में घंटों सर्चिंग कर हालात का जायजा ले चुकी है। रेंज अधिकारी नदीम खान व मनोज कुमार यादव के साथ टीम ने कैमरा ट्रैप की जांच की। कुछ में बैटरी व चिप बदलकर उन्हें फिर सक्रिय किया जा रहा है। 28 मार्च 2026 को टाइगर रिजर्व के 175 स्थानों पर दो-दो कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। 28 अप्रैल तक गणना रिपोर्ट तैयार करनी है। अधिकारियों का कहना है कि अग्निकांड के कारण कैमरा ट्रैप से बाघों की गतिविधियों का सटीक डेटा जुटाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गणना के लिए हर फुटेज को बेहद अहम माना जा रहा है। बाघ, तेंदुआ व हिरन समेत सभी वन्यजीव सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। आशंका है कि कुछ वन्यजीव विंध्य पर्वत शृंखला पार कर मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की ओर भी चले गए हैं। इससे उनकी गतिविधियों की निगरानी व गणना कार्य और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

बंगाल-तमिलनाडु चुनाव में EC का बड़ा एक्शन, अबतक एक हजार करोड़ से ज्यादा की जब्ती

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

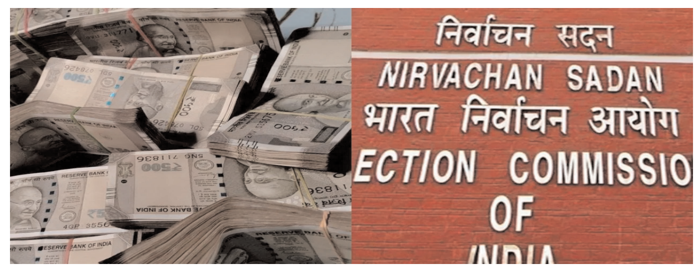

चुनाव आयोग (ECI) ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया था. उससे पहले 26 फरवरी, 2026 को इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) की घोषणा की गई थी. अब इलेक्शन कमीशन ने 2026 के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के बीच तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़ब्ती की जानकारी दी है. ECI ने कहा कि इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद से पश्चिम बंगाल में 472 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़ब्ती हुई है, जिसमें 27 करोड़ कैश, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और दूसरी बंटने वाली चीजें शामिल हैं, जबकि तमिलनाडु में 100 करोड़ केश के साथ कुल 599 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जब्ती हुई है।

दोनों राज्यों में फेयर चुनाव के लिए EC ने उठाए थे खास कदम

कमीशन ने कहा कि फ्री और फेयर चुनाव पक्का करने के लिए दोनों राज्यों में 5011 (WB में 2728 और TN में 2283) फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) तैनात की गई, ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो सके. इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर सरप्राइज नाके लगाने के लिए 5363 से ज़्यादा (WB में 3,142 और TN में 2221) स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) भी तैनात की गई थी. कमीशन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे जनता को परेशानी से बचाते हुए फ्री, फेयर और बिना किसी लालच के चुनाव पक्का करें. एनफोर्समेंट एक्टिविटी से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमेटियां भी बनाई गई हैं।

नागरिकों की शिकायतों के लिए जारी किया था C-Vigil मॉड्यूल

ECI ने नागरिकों और राजनीतिक पार्टियों से ECINET प्लेटफॉर्म पर C-Vigil मॉड्यूल के जरिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की भी अपील की है. शिकायतों को निपटाने के लिए जिला लेवल पर शिकायत कमेटियां बनाई गई हैं. पोल बॉडी ने कहा कि ये कदम चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी बनाए रखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं. बता दें, इन दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को असेंबली चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे।

चित्रकूट में युवक की संदिग्ध मौत, मां ने दोस्तों पर लगाया छत से फेंकने का आरोप

चित्रकूट। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के रुकमा बुजुर्ग के मजरा खांच में दोस्तों के साथ पार्टी के बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मां ने साथियों पर मारपीट कर छत से फेंकने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस इसे गिरने का मामला बता रही है। बुधवार की सुबह करीब एक सैकड़ा ग्रामीण ने एसपी कार्यालय के प्रदर्शन किया। घटना 16 अप्रैल की बताई जा रही है। आरोप है कि मनोज कुमार ने संतोष, पप्पू आदि दोस्तों के साथ खाना-पीना किया, जिसके बाद आपसी विवाद में खींचातानी और मारपीट हुई। मां गौरा देवी के मुताबिक बेटे को बेरहमी से पीटा गया और बाद में छत से फेंक दिया गया।

घटना छिपाने के लिए घायल को गांव के स्कूल के पास फेंककर उसके ऊपर बाइक रख दी गई। गंभीर हालत में युवक को प्रयागराज ले जाया गया, जहां मंगलवार रात करीब एक बजे उसकी मौत हो गई। गौरा देवी ने संतोष और पप्पू समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। युवक की मौत के बाद गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने एसपी आवास के सामने हंगामा कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्वजन ने चेतावनी दी कि न्याय मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटे रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बर्लिन में राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की कूटनीति की सराहना, कहा- भारत का दृष्टिकोण संतुलित और वैश्विक शांति की दिशा में अहम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति और संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण की जमकर प्रशंसा की है। बर्लिन में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक संघर्षों, विशेषकर पश्चिम एशिया संकट को सुलझाने में भविष्य में और भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

Strait of Hormuz में हुई भारतीय कूटनीति की जीत

राजनाथ सिंह ने भारत की कूटनीतिक कुशलता का एक बड़ा उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी भारतीय जहाज सुरक्षित मार्ग पाने में सफल रहे। रक्षा मंत्री ने कहा, 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जब अन्य देशों के जहाज नहीं निकल पा रहे थे, तब भारत के 7-8 जहाज वहां से गुजरने में सफल रहे।' उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भारत की तटस्थ छवि का ही परिणाम है कि न तो अमेरिका और न ही ईरान भारत को अपना दुश्मन मानता है।

शांति के लिए पीएम ने किए व्यक्तिगत प्रयास

सिंह ने वैश्विक शांति स्थापना में पीएम मोदी की सक्रिय भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से विश्व नेताओं से बातचीत की। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत कर शांति और संवाद का मार्ग चुनने की अपील की। रक्षा मंत्री ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने वैश्विक संकटों के समाधान खोजने पर चर्चा की थी।

भारत-जर्मनी संबंधों के 75 साल हुए पूरे

जर्मनी की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के प्रगाढ़ होते रिश्तों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा 'साल 2026 हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस वर्ष भारत और जर्मनी के औपचारिक राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे संबंध पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं।' राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि वह समय दूर नहीं जब भारत वैश्विक संघर्षो को समाप्त करने में और भी अधिक सफल और निर्णायक भूमिका निभाएगा।

संक्षिप्त ख़बरें

अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला, कहा- भाजपा एक 'संगठित गिरोह' है

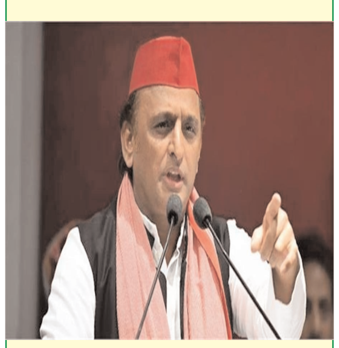

लखनऊ- समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक 'संगठित गिरोह' करार देते हुए बुधवार को कहा कि नफरत फैलाना और समाज में दूरी बनाना ही सत्तारूढ़ दल का प्रिय एजेंडा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सुरक्षित सीट पर सपा की ओर से पूर्व में खड़े किये गए प्रत्याशियों और नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा का आचरण निम्न स्तरीय है और वह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ''भाजपा संगठित गिरोह है। नफरत फैलाना और समाज में दूरी बनाना भाजपा का प्रिय एजेंडा है।

यादव ने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि देश में महिला आरक्षण कानून 2023 में ही लागू हो चुका है, लेकिन भाजपा के नेता झूठ बोलने से नहीं बाज आ रहे है। उन्होंने कहा, ''देश की जनता भाजपा के झूठ और भ्रामक प्रचार को समझ रही है। पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की एकता से घबराई भाजपा जनता के बीच इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है। भाजपा भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए झूठ का सहारा लेती है।'' यादव ने पार्टी नेताओं को भाजपा से सावधान करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव भाजपा का हारना तय है।

योगी सरकार का शराब और नशे के खिलाफ 'मास्टर प्लान', स्कूलों और पंचायतों तक पहुंचा मद्यनिषेध विभाग का जागरूकता अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 'नशामुक्त प्रदेश' की अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। मद्यनिषेध विभाग को अब केवल एक प्रशासनिक इकाई तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक चेतना जगाने वाला एक प्रभावी माध्यम बना दिया गया है। सरकार ने विभागीय ढांचे को इस तरह संगठित और सक्रिय किया है कि नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता की लहर अब गांवों की गलियों से लेकर शहरों के चौराहों तक साफ देखी जा सकती है।

जागरूकता का व्यापक जाल

योगी सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश की युवा पीढ़ी और ग्रामीण परिवारों को नशे की लत से सुरक्षित रखने पर है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर संवाद और सहभागिता आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों, रैलियों, शपथ कार्यक्रमों और सेमिनारों के जरिए युवाओं को नशे से होने वाले शारीरिक और सामाजिक नुकसान के प्रति आगाह किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं और युवा, नशे की बुराइयों को समझें और एक स्वस्थ व सक्षम उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

सुदृढ़ क्षेत्रीय नेटवर्क और निगरानी

विभागीय कार्यों को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश में एक सुव्यवस्थित नेटवर्क तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के सात प्रमुख शहरों—लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और मुरादाबाद में क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मुख्यालय प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नशामुक्ति से जुड़ी योजनाओं और प्रचार अभियानों की कमान संभाल रहे हैं। इस प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सीधा लाभ यह हुआ है कि सरकार की नीतियां अब प्रदेश के अंतिम छोर तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं।

अधिकारियों की तैनाती और प्रशासनिक मजबूती

मद्यनिषेध विभाग के ढांचे को ऊपर से नीचे तक मजबूती प्रदान करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यापक तैनाती की गई है। मुख्यालय स्तर पर राज्य मद्यनिषेध अधिकारी और उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। वहीं, फील्ड स्तर पर 7 क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, 6 उप क्षेत्रीय अधिकारी और 27 जिला मद्यनिषेध अधिकारियों की फौज तैनात है। प्रशासनिक पदों के साथ-साथ प्राविधिक पर्यवेक्षकों और सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि बजट प्रबंधन से लेकर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन तक कहीं कोई बाधा न आए।

गो-हत्या से भड़कती हैं भावनाएं, हाई कोर्ट ने याची पर लगे रासुका को सही बताते हुए सुनाया अहम फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गो-हत्या जैसे कृत्य समाज में स्वतः तीव्र भावनाएं और हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती हैं, क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से ठेस पहुंचती है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत याची की हिरासत को सही ठहराते हुए उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और संजीव कुमार की खंडपीठ ने समीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। समीर पर वर्ष 2025 में होली के दौरान एक गाय और दो बछड़ों की हत्या का आरोप है।कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य के समाज में तत्काल और व्यापक परिणाम होते हैं, जिससे लगभग हमेशा बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कती है। यह हिंसा शांत समाज को नुकसान पहुंचाती है।

खंडपीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके प्रति समुदाय इतना संवेदनशील होता है कि यदि वे सामने आते हैं तो उनमें समाज में व्यापक उथल-पुथल मचाने की अंतर्निहित क्षमता होती है, जो जीवन की सामान्य गति को प्रभावित करती है। इनमें से एक मुद्दा गाय की हत्या है। यह देखते हुए कि इस कृत्य में जीवन की सामान्य गति को बाधित करने की क्षमता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है।

खंडपीठ ने हिरासत आदेश पारित करने में हिरासत प्राधिकारी को पूरी तरह से उचित पाया। प्राधिकारी ने यह सोचकर आदेश दिया कि जेल से रिहा होने पर याचिकाकर्ता सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इसी के साथ खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। समीर की हिरासत का आदेश शामली के जिला मजिस्ट्रेट ने रासुका की धारा 3(3) के तहत दिया था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने भी सही ठहराया था।

ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला, IPAC छापेमारी केस में सुप्रीम कोर्ट की सीएम को फटकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बंगाल IPAC छापेमारी केस की सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ी सख्त टिप्पणी की. स्ट ने कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करता है, तो इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद नहीं कहा जा सकता. स्ट ने कहा कि एक मौजूदा सीएम जांच में दखल देंगी ऐसा सोचा नहीं था. संविधान विशेषज्ञों ने भी ऐसा नहीं सोचा था. एक तरह से ममता ने लोकतंत्र को खतरे में डाला है. सुप्रीम कोर्ट ने छापे के दौरान ममता के मौके पर पहुंचने पर उन्हें फटकार भी लगाई है. दरअसल, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. इन अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार I-PAC के घर पर ईडी के छापे में बाधा डालने का आरोप था. ईडी अधिकारियों द्वारा भी एक संबंधित रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।

बंगाल सरकार के तर्क पर जताई असहमति

राज्य सरकार यानी टीएमसी की वकील ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ईडी द्वारा दायर रिट याचिका की वैधता पर सवाल उठाया. राज्य के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि यह मामला मूलतः राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए. इस तर्क से असहमत होते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि इसमें राज्य का क्या अधिकार निहित है? यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद नहीं है. आप बीच में नहीं आ सकते. किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री किसी जांच के बीच में आ जाए और आप कहें कि यह मूलतः राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद है?

पूरी व्यवस्था और पूरे लोकतंत्र को दांव पर लगाया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आपत्तिजनक सामग्री भी ले जाई गई थी. तब न्यायमूर्ति कुमार ने डीजीपी की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है. यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य है जो संयोगवश एक राज्य का मुख्यमंत्री है, और उसने पूरी व्यवस्था और पूरे लोकतंत्र को दांव पर लगा रखा है. आप कह रहे हैं कि यदि यह सब सुनवाई योग्य है तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत नहीं बल्कि केवल अनुच्छेद 132 के तहत सुनवाई योग्य माना जा सकता है. सॉलिसिटर जनरल आपने हमें केशवानंद भारती और सीरवाई के उदाहरण दिए हैं. लेकिन उनमें से किसी ने भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में एक दिन ऐसा आएगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री किसी अन्य एजेंसी के कार्यालय में जाएगा।

मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग खारिज

इससे पहले टीएमसी की वकील मेनका गुरुस्वामी ने इस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए और मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा बड़ा संवैधानिक सवाल है जिसे बड़ी बेंच को भेजा जाए? अदालत ने साफ किया कि हर अनुच्छेद 32 की याचिका को बड़ी बेंच को नहीं सौंपा जा सकता. यह सुनवाई ईडी अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर हो रही है जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई है।

पृथ्वी दिवसः पर्यावरण संरक्षण की चेतना और मानव अस्तित्व का आधार

22 अप्रेल विश्व पृथ्वी दिवस

हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के लिए चेतावनी और संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जिस पृथ्वी पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के विकास ने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमने प्रकृति का अत्यधिक दोहन भी किया है, जिसके कारण आज पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

पृथ्वी दिवस की शुरुआत वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन द्वारा की गई थी। 1969 में कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा में हुए भीषण तेल रिसाव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को एक बड़े स्तर पर 'टीच-इन' कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन को सफल बनाने में डेनिस हेज़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आयोजन इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि यह एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

पृथ्वी दिवस मनाने का विशेष कारण आज की पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान समय में पृथ्वी अनेक समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन प्रमुख हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जहां एक ओर विकास को गति दी है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी दिवस हमें यह चेतावनी देता है कि यदि हमने समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाला भविष्य अत्यंत कठिन हो सकता है।

पृथ्वी दिवस का उद्देश्य केवल समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं है, बल्कि लोगों को समाधान के लिए प्रेरित करना भी है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण से संबंधित संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।

समय के साथ पृथ्वी दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। 1990 में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और आज यह 190 से अधिक देशों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस' के रूप में मान्यता देकर इसकी वैश्विक पहचान को और सुदृढ़ किया। इसके

अतिरिक्त, 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हर वर्ष पृथ्वी दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है, जो वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, 2025 की थीम 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह' नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें यह संदेश देती है कि हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ और टिकाऊ स्रोतों को अपनाना चाहिए, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पृथ्वी दिवस का महत्व इस बात में भी निहित है कि यह हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संगठनों का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करके भी पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, कचरे का उचित निपटान करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ये छोटे कदम मिलकर एक बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।

पृथ्वी दिवस हमें यह भी सिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम केवल विकास पर ध्यान देंगे और पर्यावरण की उपेक्षा करेंगे, तो यह विकास स्थायी नहीं रहेगा। सतत विकास की अवधारणा इसी संतुलन पर आधारित है, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। यह दिन हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की कुंजी है।

आज के समय में पृथ्वी दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सतत आंदोलन बन चुका है, जो पूरे वर्ष लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि हम इसके संरक्षक हैं और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। अंततः, पृथ्वी दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि यदि हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं, तो हमें अभी से प्रयास शुरू करने होंगे। यह केवल सरकारों या बड़े संगठनों का कार्य नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। जब हम सभी मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे, तभी हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण का निर्माण कर पाएंगे। यही पृथ्वी दिवस का वास्तविक उद्देश्य और सार है।

कांतिलाल मांडोत

नवप्रवर्तन सृजनात्मकता की नई धारा

(नवाचार की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका)

जीवन ही चलने का नाम है,गति ही जीवन है। सभी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतियों ने यह माना है कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के रचनात्मक विचार नयापन लाते हैं उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसे ही नवप्रवर्तन माना जाता है, नवप्रवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच एक बड़ी लाइन खींचना है। इसीलिए यह माना जाता है कि नवप्रवर्तन समाज में 3% नवाचार का निर्धारित है, शेष 97 प्रतिशत परंपरावादी विचारों के लिए है। पुराने समय से ही आर्थिक समृद्धि में नवप्रवर्तन की भूमिका को स्वीकार किया गया है चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्य क्रांति का औद्योगिक क्रांति में बदलना इन सभी में नवप्रवर्तन ने प्रेरक का काम किया है। हम चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुसुप्त होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके विचार करोड़ों डॉलर के हो । वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। नवप्रवर्तन या नवाचार से मैं सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को न्यूनतम किया है, बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है,जबकि भारत में यह तबाही ला सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है। जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास आर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कृषी क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नवप्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृषि में भी आधुनिकीकरण और पाश्चात्य उपकरण का प्रादुर्भाव भी नवीन नवाचार के कारण संभव हुआ है। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण करने वाले राज्य में बदलने की नवप्रवर्तन की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसके कारण भार मानी जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाली की भूमिका में आ चुकी हैं। इसी तरह न्यायिक क्षेत्र में जनहित याचिका की अवधारणा ने न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है। यह अलग बात है कि केवल नवप्रवर्तन को ही एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है। पश्चिमी देशों में नवीन विचारों को जगह देने के कारण वहां पुनर्जागरण आया है। हमें समाज को नव परिवर्तन की तरफ जागरूक करने की आवश्यकता होगी और नवप्रवर्तन में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देकर उस और और ज्यादा विचार-विमर्श कर नीति बनाने की आवश्यकता होगी। इस तरह हमें महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार अपने या दूसरों के विचारों नवप्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

संजीव ठाकुर

साइबर अपराध का बदलता चेहरा

डिजिटल युग ने मानव जीवन को जितना सरल और सुविधाजनक बनाया है, उतना ही जटिल और जोखिमपूर्ण भी बना दिया है। आज बैंकिंग से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी और संचार तक लगभग हर काम इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। इस तेज बदलाव के बीच अपराधियों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं। पहले जहां चोरी और धोखाधड़ी के लिए भौतिक उपस्थिति जरूरी होती थी, वहीं अब एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति किसी को भी ठग सकता है। हाल के वर्षों में डिजिटल ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है और चिंता की बात यह है कि इनका शिकार केवल अनपढ़ या ग्रामीण लोग ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित और समझदार लोग भी हो रहे हैं।

डिजिटल ठगी के नए तरीकों में सबसे खतरनाक रूप से उभर कर सामने आया है तथाकथित डिजिटल अरेस्ट। यह एक ऐसा छल है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी का कर्मचारी या किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को डराता है। उसे बताया जाता है कि उसके नाम पर कोई गंभीर अपराध दर्ज है जैसे धन शोधन, अवैध लेनदेन या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता। इसके बाद वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से व्यक्ति को कई घंटों तक अपने नियंत्रण में रखा जाता है। उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह जांच के दायरे में है और उसे कहीं जाने या किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। इस दौरान उसे मानसिक दबाव में रखा जाता है और अंततः पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में साइबर अपराध के लगभग 15 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 20 लाख के आसपास पहुंच गई। इनमें से एक बड़ा हिस्सा वित्तीय ठगी से जुड़ा है। औसतन हर दिन हजारों लोग इस तरह के अपराधों का शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में एक ही व्यक्ति से 50000 से लेकर 5000000 रुपये तक की ठगी की गई है। यह आंकड़े केवल दर्ज मामलों के हैं, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग शर्म या डर के कारण शिकायत ही नहीं करते।

डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले इतने प्रभावी इसलिए होते हैं क्योंकि वे मानव मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब किसी व्यक्ति को अचानक यह बताया जाता है कि वह किसी गंभीर अपराध में फंस गया है, तो उसका पहला भाव डर और घबराहट का होता है। अपराधी इसी डर का फायदा उठाते हैं। वे अपनी भाषा, पहनावा और संवाद शैली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें वास्तविक अधिकारी समझने लगता है। कई बार वे नकली पहचान पत्र, कार्यालय का बैकग्राउंड और वर्दी का भी उपयोग करते हैं ताकि उनकी बात और अधिक विश्वसनीय लगे।

इस प्रकार की ठगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें समय का दबाव बनाया जाता है। पीड़ित को सोचने या सलाह लेने का अवसर नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता है कि यदि उसने तुरंत सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मानसिक दबाव में व्यक्ति बिना सत्यापन किए ही पैसे भेज देता है। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक सजगता और धैर्य भी उतना ही

आवश्यक है।

भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है जहां तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और डिजिटल जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अपराधों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और तकनीक का तेजी से बदलता स्वरूप है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल ठगी को रोकने के लिए केवल कानून और तकनीक पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक करना आवश्यक है। परिवारों में इस विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों और युवाओं को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी शुरुआत से ही सतर्क रहे।

व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सरल सावधानियां अपनाकर इस प्रकार की ठगी से बचा जा सकता है। सबसे पहले किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर तुरंत विश्वास न करें। यदि कोई खुद को अधिकारी बताकर डराने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान की पुष्टि करें। किसी भी स्थिति में अपने बैंक खाते, पासवर्ड, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। यदि कोई आपसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है तो पहले अपने परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से पैसे नहीं मांगती।

डिजिटल ठगी का बढ़ता हुआ खतरा केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करता है। जब लोग बार बार ऐसे अपराधों का शिकार होते हैं तो उनका विश्वास संस्थाओं और तकनीक दोनों से उठने लगता है। यह स्थिति विकास की गति को भी प्रभावित कर सकती है क्योंकि डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में लोग हिचकिचाने लगते हैं।

इस समस्या का समाधान केवल तकनीकी उपायों में नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी में निहित है। सरकार, संस्थाएं और आम नागरिक सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। जागरूकता, सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ही इस लड़ाई के सबसे प्रभावी हथियार हैं। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो डिजिटल ठगी का यह जाल और अधिक व्यापक और खतरनाक हो सकता है।

अंततः यह समझना जरूरी है कि डिजिटल युग में सुरक्षा केवल पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। जितना हम तकनीक का उपयोग करते हैं, उतना ही हमें उसके जोखिमों को समझना भी आवश्यक है। सावधानी और समझदारी के साथ ही हम इस अदृश्य खतरे से स्वयं को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं।

महेन्द्र तिवारी

आरोपों की आवाज़ ऊंची थी, पर निर्णय की नींव गहरी थी

[न्याय की चौखट पर ठहरे सवाल, लेकिन झुका नहीं कानून]

[आशंका बनाम प्रमाणः अदालत ने खींच दी न्याय की असली रेखा]

कभी-कभी अदालतों में सिर्फ़ मुकदमे नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सिद्धांतों की भी असली परीक्षा होती है– और 20 अप्रैल 2026 को दिल्ली में यही तस्वीर दिखी। आरोपों और संस्थागत गरिमा के बीच सीधा टकराव था, और सवाल था कि न्याय किस आधार पर टिकेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के कक्ष में जब अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा से खुद को मामले से अलग करने की मांग उठाई, तो बहस एक साधारण कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़कर न्यायिक निष्पक्षता पर केंद्रित हो गई। लेकिन सुनवाई के अंत में अदालत ने रिक्यूसल याचिका खारिज कर स्पष्ट कर दिया कि न्याय न आशंकाओं पर चलता है, न संकेतों पर डगमगाता है; वह ठोस प्रमाण, तर्क और कानून की मजबूत नींव पर टिका होता है।

बहस की दिशा अचानक तब बदली, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने अतिरिक्त हलफ़नामे के माध्यम से मुद्दे को जज के निजी पेशेवर संबंधों तक विस्तार दे दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के बेटे और बेटी सरकारी पैनल के वकील हैं और उन्हें तुषार मेहता जैसे सॉलिसिटर जनरल के जरिए लगातार काम मिलता है, जो इसी मामले में जांच एजेंसियों का पक्ष रख रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई पर 'उचित संदेह' जताते हुए जज के अलग होने की मांग की। यह दलील सीधे न्यायपालिका की निष्पक्षता और उसकी सार्वजनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली थी। केजरीवाल की दलील महज़ एक नेता की व्यक्तिगत आपत्ति नहीं, बल्कि उस व्यापक और गहरी लोकतांत्रिक चिंता की अभिव्यक्ति है कि न्याय सिर्फ़ निष्पक्ष हो ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे। खासकर तब, जब मामला राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील हो और उसमें केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय रूप से शामिल हों, हर संभावित जुड़ाव–चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष–स्वाभाविक रूप से सवाल और शंकाएँ पैदा कर सकता है। इसी नजरिए से देखें तो अरविंद केजरीवाल का तर्क पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता; यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और जवाबदेही की वैध मांग का भी संकेत देता है।

अदालत ने जब इस पूरे तर्क-विन्यास को गहराई से परत-दर-परत खंगाला, तो उसकी कानूनी मजबूती खुद ही सवालों के घेरे में आ गई। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने स्पष्ट कहा कि महज़ आशंका या संकेत किसी न्यायाधीश को हटाने का वैध आधार नहीं बन सकते, क्योंकि इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया अस्थिर और संदिग्ध हो जाएगी। उन्होंने यह भी चेताया कि अगर ऐसे तर्कों को मान्यता मिल गई, तो हर मुकदमे में जजों के निजी जीवन और पारिवारिक संबंधों को हथियार बनाया जाने लगेगा। इसी निर्णायक मोड़ पर अदालत ने न केवल दलीलों को सिरे से खारिज किया, बल्कि स्पष्ट और सख्त शब्दों में आदेश सुनाया–याचिका खारिज की जाती है।

बहस के बीच एक ऐसा निर्णायक क्षण आया, जिसने पूरे विवाद का केंद्र ही बदल दिया–' अगर राजनेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं, तो जजों के बच्चे वकालत क्यों नहीं कर सकते?' जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की यह टिप्पणी महज़ एक प्रतिवाद नहीं, बल्कि एक गहरे संवैधानिक सिद्धांत की स्पष्ट और सशक्त पुनर्पुष्टि थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर पेशा चुनने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सीधे-सीधे मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, जिसे किसी मुकदमेबाज़ की रणनीति या सुविधा के लिए सीमित नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ़ अदालत के निर्णय तक सीमित कर देना वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देना होगा। अरविंद केजरीवाल का पक्ष साफ़ संकेत देता है कि राजनीति और न्यायपालिका के बीच अविश्वास की खाई लगातार गहराती जा रही है। जब एक निर्वाचित नेता बार-बार अपने खिलाफ़ कार्रवाई को राजनीतिक करार देता है, तो यह केवल आरोप नहीं, बल्कि उस व्यापक माहौल की झलक है जहाँ संस्थाओं पर भरोसा डगमगाने लगता है। ऐसे परिदृश्य में अदालत पर भी यह अतिरिक्त दायित्व आ जाता है कि वह सिर्फ़ निष्पक्ष रहे ही नहीं, बल्कि अपनी निष्पक्षता को स्पष्ट, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से प्रदर्शित भी करे। अदालत ने इस पूरे विवाद को केवल तात्कालिक नहीं, बल्कि उसके व्यापक और दूरगामी प्रभावों के संदर्भ में देखा। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने स्पष्ट कहा कि यदि केवल आशंका या अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर फैसले होने लगें, तो न्यायपालिका की बुनियाद ही डगमगा सकती है। उन्होंने अपने आदेश में रेखांकित किया कि आरटीआई या परोक्ष जानकारियों के आधार पर किसी दुरुपयोग का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने की प्रवृत्ति शुरू हो गई, तो हर जज और उसके परिवार पर संदेह का वातावरण बनेगा, जो अंततः लोकतंत्र के लिए गंभीर रूप से घातक साबित होगा। यह घटनाक्रम लोकतंत्र के उस जटिल और नाजुक संतुलन को उजागर करता है, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग, संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्थिरता से टकराती नजर आती है। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होना केवल एक साधारण कानूनी फैसला नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और मजबूत सिद्धांत की स्थापना है–कि न्यायपालिका आरोपों या दबाव के आगे नहीं झुकेगी। साथ ही, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे विवाद यह संकेत देते हैं कि आपसी विश्वास बहाल करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी सीमाओं, जिम्मेदारियों और आचरण की मर्यादाओं को समझना और मानना होगा।

जब बहस थमती है और फैसले दर्ज हो जाते हैं, तब असली सवाल सामने आता है– न्याय की विश्वसनीयता किस पर टिकी है। इस पूरे प्रकरण ने साफ़ किया कि न्याय केवल निर्णयों से नहीं, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता और भरोसे से बनता है। अदालत ने याचिका खारिज कर यह रेखांकित कर दिया कि ठोस प्रमाण के बिना कोई भी आशंका न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती। फिर भी, यह प्रश्न बना रहता है कि क्या हमारी राजनीतिक और न्यायिक संस्थाएं वह भरोसा कायम कर पा रही हैं, जिसकी एक सुदृढ़ लोकतंत्र को आवश्यकता है। अंततः, यही निष्कर्ष उभरता है–संतुलन, पारदर्शिता और सिद्धांतों के बीच सटीक तालमेल ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

जिनके हाथों में आतंक की चिंगारी, वही अब शांति की मशाल लिए नाच रहे हैं!

पिछले कुछ वर्षों का वैश्विक परिदृश्य किसी जीवंत त्रासदी से कम नहीं रहा। दुनिया ने युद्धों को केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं, बल्कि 'लाइव प्रसारण' के रूप में देखा और उसके दंश को प्रत्यक्ष रूप से भोगा। विडंबना यह है कि जिन राष्ट्रों का इन संघर्षों से प्रत्यक्ष सरोकार नहीं था, वे भी महँगाई, ऊर्जा-संकट और पर्यावरणीय क्षति के रूप में इस वैश्विक 'युद्ध-कर' को चुकाने के लिए विवश हैं। इन युद्धों के पीछे विस्तारवाद, वैश्विक वर्चस्व की होड़, परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा और नाटो जैसे संगठनों में शामिल होने की प्रतिस्पर्धा स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ विश्लेषक इन्हें 'ग्लोबल वेपन एक्सपो' तक कहने लगे हैं, जहाँ महाशक्तियाँ अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हुए कमजोर देशों को 'टेस्टिंग ग्राउंड' में बदल रही हैं। इस बाजारवादी युग में मानवता और प्रकृति दोनों ही 'कोलेटरल डैमेज' बनकर रह गए हैं। वर्तमान में ईरान, अमेरिका और इजराइल का त्रिकोण वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान पर हिज्बुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि ईरान इन संगठनों के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। यूरेनियम संवर्धन के सहारे क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की उसकी आकांक्षा है।

हालिया सैन्य कार्रवाइयों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत को बहुत ज्यादा क्षति पहुँचाई है, फिर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है,हार मानने के लिए राजी नहीं। अपितु 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के माध्यम से वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर उसने अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया है। इस नई व्यवस्था का प्रभाव अब लगभग पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है-आर्थिक दबाव, जन असंतोष और युद्ध-विरोधी स्वर तेजी से उभर रहे हैं। यही कारण है कि आक्रामक शक्तियाँ अब 'सम्मानजनक शांति' की राह तलाश रही हैं। इस परिदृश्य का सबसे विडंबनापूर्ण पक्ष तब सामने आता है, जब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का दावा करने वाला अमेरिका, ईरान से संवाद के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाता है। वही पाकिस्तान, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की पनाहगाह रहा है। ओसामा बिन लादेन को शरण देने वाले देश के माध्यम से शांति की पहल, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नैतिक द्वंद्व को उजागर करती है। यह स्थिति कई प्रश्न खड़े करती है,क्या आतंकवाद की परिभाषा देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है? क्या वैश्विक शक्तियाँ अब सिद्धांतों के बजाय स्वार्थों से संचालित हो रही हैं? यदि आतंक की फैक्ट्री ही शांति का शोरूम खोलने लगे, तो यह मान लेना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कहीं न कहीं केवल दिखावा बनकर रह गया है।

पाकिस्तान में आयोजित शांति वार्ता का विश्लेषण बताता है कि अमेरिका 'प्रतिबंधों की तलवार' और 'शांति के प्रस्ताव' दोनों के साथ इस वार्ता में उपस्थित हुआ, जबकि ईरान ऐस तरह से शर्तें रखी, मानो वह पराजित नहीं, बल्कि निर्णायक स्थिति में हो। यह पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जटिलता और अवसरवादिता को दर्शाती है। वहीं इजराइल ने इस प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखते हुए संकेत दिया है कि बारूद की गंध के बीच शांति संभव नहीं। वहीं चीन और रूस जैसे महाशक्तियां इस पूरे घटनाक्रम में ऊपर से मौन दर्शक बने रहकर रणनीतिक लाभ लेने की स्थिति में हैं,अपना उल्लू सीधा करते हुए दिखाई देते हैं। सही मायने में देखा जाए तो आज विश्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ 'आतंकवाद' की परिभाषा सुविधानुसार बदल दी जाती है। जब तक हिंसा पड़ोसी के घर तक सीमित रहती है, वह स्वतंत्रता के लिए 'संघर्ष' कहलाती है; लेकिन जब वही अपने घर तक पहुँचती है, तो 'आतंकवाद' बन जाती है। यही दोहरा मापदंड वैश्विक शांति और विश्व से आतंकवाद की समाप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जिस पाकिस्तान को कल तक 'आर्थिक रूप से जर्जर' और आतंकवाद का आश्रयदाता कहकर विश्व समुदाय कठघरे में खड़ा करता था, आज वही शांति की मशाल थामे मध्यस्थ बनने का दावा कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का वह विचित्र रंगमंच है, जहाँ पात्र नहीं, भूमिकाएँ बदलती हैं और सत्य अक्सर पर्दे के पीछे छूट जाता है।जब कातिल ही न्यायाधीश की कुर्सी पर आसीन हो जाए, तो यह केवल विडंबना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गहरी विकृति का संकेत है। यह वह दौर है जहाँ सिद्धांतों की नहीं, अवसरों की बोली लगती है; जहाँ नैतिकता नहीं, बल्कि रणनीतिक सुविधा ही निर्णयों का आधार बनती है। ऐसे में प्रश्न केवल पाकिस्तान का नहीं, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था का है, जो समय-समय पर अपने ही घोषित मूल्यों से समझौता कर लेती है। शायद यही कूटनीति का सबसे कटु सत्य है।

डा. मनमोहन प्रकाश

पारिवारिक कलह से रिश्तों का रोज़ होता पतन

भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन देश में बढ़ते अपराध–विशेषकर घरेलू और पारिवारिक हिंसा के जघन्य मामलों–में निरंतर वृद्धि होना एक सभ्य समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज के आधुनिक दौर में जब भी हम समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनलों से रूबरू होते हैं, तो राजनीति से इतर आपराधिक घटनाओं और पारिवारिक कलह से जुड़ी खबरों का प्रतिशत लगातार बढ़ता दिखाई देता है। मीडिया द्वारा इन घटनाओं को प्रमुखता से दिखाना अब मजबूरी बन गई है, क्योंकि देश के लगभग हर धर्म, वर्ग और समाज में पारिवारिक हिंसा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो कई बार जघन्य अपराधों का रूप ले लेता है। भारत विश्व को शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला देश माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे अपने ही परिवारों में रिश्तों के बीच दूरियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि साथ बैठकर भोजन करना भी कठिन होता जा रहा है। सिर्फ भाई-भाई के रिश्ते ही नहीं, बल्कि पति-पत्नी के संबंधों में भी जिस गति से अलगाव बढ़ रहा है और उसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं, वह पूरे समाज के लिए गहन चिंतन का विषय है। यह स्थिति हर धर्म, हर वर्ग और हर व्यक्ति को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है।

आधुनिकता की दौड़ में हमने नई पीढ़ी को महंगी शिक्षा और भौतिक सुख-सुविधाएँ तो भरपूर दी हैं, लेकिन उन्हें सहनशीलता, धैर्य, अपनत्व, विनम्रता और परिवार को साथ लेकर चलने के संस्कार देने में हम कहीं पीछे रह गए हैं। परिणामस्वरूप, नवपीढ़ी में धैर्य और सहनशीलता का अभाव बढ़ रहा है, जो पारिवारिक कलह को जन्म देकर कई बार गंभीर अपराधों में बदल जाता है। आज कोई भी समाज या व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह पारिवारिक कलह से पूरी तरह मुक्त है। जो घटनाएँ आज हम समाचारों में देख-सुन रहे हैं, वे कल किसी भी परिवार की वास्तविकता बन सकती हैं। कहीं पैसों के विवाद, कहीं अवैध संबंधों की आशंका, कहीं कर्ज का दबाव, तो कहीं नशे की लत या पारिवारिक हस्तक्षेप–इन सभी कारणों से महानगरों से लेकर गाँवों तक रिश्तों का पतन तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई बार कम उम्र और कम समझ वाले लोग भी संदेह या आवेग में आकर अपने ही जीवनसाथी की हत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं। वहीं, कर्ज और पारिवारिक तनाव से परेशान होकर अपने ही मासूम बच्चों की हत्या कर आत्महत्या करने की घटनाएँ भी समाज को झकझोर देती हैं।

यह भी एक कटु सत्य है कि पारिवारिक कलह अब केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रही। जहाँ गरीब परिवारों में इसे आर्थिक तंगी का परिणाम माना जाता है, वहीं संपन्न और भौतिक रूप से समृद्ध घरों से उठती कलह की आवाजें रिश्तों के आंतरिक विघटन की ओर संकेत करती हैं। हर दिन अवैध संबंधों की शंका और अविश्वास के चलते प्रेम, विश्वास और अपनत्व जैसे रिश्तों का गला घोंटने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग को पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। यदि हम परिवार की खुशहाली, सौहार्द और विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो मजबूत और संतुलित दाम्पत्य जीवन पर सामूहिक मंथन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।

अरविंद रावल

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

तंबौर में तीन सभासद मनोनीत, एसडीएम ने दिलाई शपथ

लहरपुर, तंबौर क्षेत्र में शासन द्वारा तीन सभासदों की मनोनीति की गई। नामित सभासदों में अजय पटेल, राम सिंह वर्मा और मनोज नाग शामिल हैं। लहरपुर में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम ने सभी तीनों नामित सभासदों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष जयकुमार वर्मा मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष तंबौर तैय्यबुन निशा, सकरन मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्या, जिला प्रतिनिधि अजय पटेल, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश शुक्ला और पूर्व मंडल अध्यक्ष तंबौर नगर टेनी रस्तोगी ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शासन की इस पहल से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मनोनीत सभासदों ने शपथ ग्रहण के बाद क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सलेथू में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

महराजगंज/रायबरेली। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सलेथू की छात्रा शिवानी सिंह पुत्री राकेश सिंह का यूपी पीसीएस-2024(असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी) पद पर चयन होने पर विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवानी सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा एन.एस.पी.एस. सलेथू से ग्रहण की। इन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा-2014 तथा इंटरमीडिएट-2016 में उत्तीर्ण की थी। छात्रा का पीसीएस में चयन होने पर विद्यालय परिवार गौरवान्वित है। आयोजित समारोह में शिवानी सिंह ने विद्यालय के छात्रों को अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रेरित किया व बताया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे अपनी रणनीति बनानी होगी साथ ही उपस्थित छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनको प्रोत्साहित किया। प्रधानाचार्य राजीव सिंह ने बताया कि शिवानी सिंह हमारे विद्यालय की होनहार व प्रतिभावान छात्रा रही है। छात्रा ने अपने अथक प्रयास और समर्पण से विद्यालय का नाम रोशन किया है जिससे हम और हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रा शिवानी सिंह विद्यालय के लिए प्रेरणा श्रोत है उनकी इस सफलता से अन्य छात्र-भी प्रेरित होंगे। इस कार्यक्रम में उप- प्रधानाचार्या रजनी श्रीवास्तव, शिक्षक- शिक्षिकाएं ,छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

परसेंडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, सिर धड़ से हुआ अलग

शिनाख्त की कोशिशों में जुटी जीआरपी आत्महत्या की आशंका

तालगांव सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के गहनता से जांच अंतर्गत परसेंडी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह लगभग 10:30बजे उस समय हुआ जब जननायक एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। ट्रेन निकलने के बाद राहगीरों ने युवक का शव पटरी पर पड़ा देखा। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया था। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। घटना की सूचना के करीब दो घंटे बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) मौके पर पहुंची। जीआरपी दरोगा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज या सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस अन्य सभी पहलुओं पर भी कर रही है।

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि कैलाश प्रसाद पुत्र रामलाल, निवासी ग्राम भरसवा, फतेहपुर के पुत्र प्रदीप कुमार का जन्म 04/06/2009 को हुआ था (माताः पितनी देवी)। जानकारी न होने के कारण इनका जन्म पंजीकरण नहीं कराया जा सका था, जिसे अब दर्ज कराया जा रहा है। यदि किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो, तो एक सप्ताह के भीतर सक्षम कार्यालय या न्यायालय में सूचित करें।

सूचना

सूचित किया जाता है कि उपजिलाधिकारी न्यायालय तहसील लंभुआ में वाद संख्या 20250468031027 प्रेमा बनाम रजई आदि की सुनवाई आगामी 23 अप्रैल 2026 को सुनिश्चित हुई है। जिसमें प्रेमा, रजई, पुद्ध, सुरेश (दोनों पक्ष) आदि समय से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

बिराहिमपुर ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था ध्वस्त, प्रधान व सचिव पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश, प्राथमिक विद्यालय बना जंगल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बिराहिमपुर ग्राम पंचायत इन दिनों बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान रामशंकर और पंचायत सचिव पर घोर लापरवाही और अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में महीनों से नियमित साफ-सफाई नहीं कराई गई है, जिसके चलते पूरे पंचायत में गंदगी का अंबार लग गया है और लोगों का जीवन दूभर हो गया है।

ग्राम पंचायत के रामपुर बस्ती मजरा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। यहां की नालियां पूरी तरह जाम होकर बजबजा रही हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों और गलियों में फैल रहा है। दुर्गंध के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो प्रधान ने कोई ध्यान दिया और न ही पंचायत सचिव ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया।

वहीं शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालय की हालत भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। विद्यालय परिसर में जगह-जगह झाड़ियां और घास उग आई हैं, जिससे पूरा परिसर जंगल जैसा नजर आने लगा है। साफ-सफाई के अभाव में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां तैनात शिक्षक खुद अपने निजी खर्च से मजदूर लगाकर विद्यालय की सफाई कराने को मजबूर हैं, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान रामशंकर दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या या शिकायत लेकर उसके पास पहुंचता है, उसे डराने-धमकाने की कोशिश की जाती है। इस कारण लोग खुलकर अपनी समस्याएं रखने से भी डरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पंचायत में तैनात सफाईकर्मियों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रधान केवल अपने चहेते और करीबी लोगों के घरों व आसपास ही सफाई कराता है, जबकि बाकी गांव गंदगी और अव्यवस्था से जूझता रहता है। इससे गांव में असमानता और नाराजगी का माहौल बना हुआ है।

ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने को भी मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर सरफराज की याचिका खारिज, उसरी चट्टी हत्याकांड में मुकदमा जारी

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गाजीपुर के उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के कथित शार्प शूटर सरफराज अंसारी उर्फ मुन्नी के खिलाफ चल रही अभियोजन की कार्यवाही को समाप्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में विचारण कोर्ट के सामने आरोपपत्र दाखिल होकर याची पर आरोप तय हो चुके हैं और घटना में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय की गवाही भी हो चुकी है। इसलिए ऐसे में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत दखल देकर पूरी अभियोजन कार्यवाही खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने सरफराज अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है।याची की ओर से कहा गया था कि घटना 2001 की है, जिसमें मुख्तार अंसारी के गुट पर बृजेश सिंह गुट ने बड़ा हमला किया था। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी। बृजेश के साथ कथित रूप से घटना में शामिल मनोज राय की भी मौत हो गई थी। मनोज राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय ने 2023 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने पर मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ 2001 की घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था कि मनोज राय को बिहार के बक्सर से उठाकर मुख्तार के गुर्गो ने उसकी हत्या करके उसरी चट्टी हत्याकांड में मरना बता दिया था।

लोकतंत्र की सशक्त सारथी बनेंगी महिलाएंः रमेश वाजपेयी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। स्त्री शक्ति का उत्थान और बालिकाओं की सुरक्षा वर्तमान शासन तंत्र की प्राथमिक अधिमानताओं में सर्वोपरि है। महिलाओं के चहुंमुखी विकास और विधायी प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवर्तित नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक युगांतरकारी हस्तक्षेप है। यह विचार स्थानीय सीता इंटर कॉलेज के शास्त्री सभागार में व्यक्त किए गए। अवसर था राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की इकाई द्वारा आयोजित विशेष जागरूकता अभियान का, जहाँ प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी 'विरल' छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं को संबोधित कर रहे थे। प्रधानाचार्य ने बल दिया कि आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने छात्राओं को केवल शैक्षिक अर्जन तक सीमित न रहकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वर्ष 2023 के इस ऐतिहासिक अधिनियम की व्याख्या करते हुए उन्होंने इसे महिलाओं के राजनीतिक व सामाजिक सशक्तीकरण का आधार स्तंभ बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को स्वावलंबन और नेतृत्व कौशल विकसित करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। समारोह के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

इस गरिमामयी आयोजन में उप-प्रधानाचार्य यशपाल वर्मा, एनएसएस के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शिवसेवक मिश्र, सांस्कृतिक प्रभारी प्रतिभा सिंह सहित अनीता वर्मा, राजकुमारी वर्मा एवं संजू रस्तोगी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं एवं छात्राओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई।

न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल में समर फन कैंप का भव्य आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज, रायबरेलीः न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय समर फन कैंप का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ एनएसपीएस तेजगाव के प्रधनाचार्य इंद्र विक्रम सिंह व एनएसपीएस विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवांग अवस्थी ने फीता काट कर किया। कैंप के दौरान विद्यार्थियों के लिए अनेक रोमांचक एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें वॉटर रोलर, ज़ॉर्बिंग, ट्रेम्पोलिन, पूल क्रॉसिंग, एडवेंचर माउंटेन बाइक, पॉटरी, किड्स बाउंसी, बिग बाउंसी, सूमो रेसलिंग, रेन डांस, पूल पार्टी, फोम पार्टी, नॉकआउट बाउंसी, टेंडम साइकिल, बर्मा ब्रिज कमांडो क्रॉसिंग तथा पप्पेट शो प्रमुख रहे।

इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ आनंद उठाया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, साहस, रचनात्मकता एवं टीम भावना का विकास करना था, जिसमें यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवांग अवस्थी ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस प्रकार के फन कैंप बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्त कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र अंशुमान भदौरिया, शिवांश त्रिपाठी, भौमिक त्रिवेदी, आधा यादव,अदिती आदि को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, जिससे यह आयोजन यादगार बन गया। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक -शिक्षिकाएं व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बाराबंकी-बहराइच हाईवे निर्माण में अटका पेच, अलाइनमेंट बदला तो टूटेंगे सैकड़ों मकान

लखनऊ। बाराबंकी से बहराइच के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की हरी झंडी कैबिनेट से भले मिल गई हो, लेकिन वन विभाग की अनुमति मिलना बाकी है। अक्टूबर 2026 से काम शुरू होना है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक किए गए कई पत्राचार के बाद भी वन विभाग से एनओसी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सेकेट्री फॉरेस्ट राज्य सरकार से क्लीयरेंस मिलना है। छह लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग मुस्ताफाबाद से कैसरगंज होते हुए बहराइच तक जाएगा। इस रास्ते में वन विभाग की 70 हेक्टेयर जमीन है। वन विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के अलाइनमेंट का बदलवाना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग में नौ हजार पेड़ आ रहे हैं, जिन्हें सड़क बनाते वक्त काटना ही पड़ेगा और कई हेक्टेअर जमीन भी जाएगी। वहीं, वन विभाग इस अलाइनमेंट को बदलवाने का प्रयास कर रहा है। एनएचएआई का तर्क है कि पीएमओ कार्यालय से अलाइनमेंट की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में अलाइनमेंट में कोई बदलाव संभव नहीं है। अगर अलाइनमेंट बदलता है तो शहर के भीतर से निकलेगा और सैकड़ों मकान गिराए जाएंगे, इससे प्रोजेक्ट की लागत कई सौ करोड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट विलंब से शुरू होने की संभावना है।

मलिहाबाद में 'मलिहा पासी स्मृति द्वार' को लेकर गहराया विवाद, सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे भड़काऊ पोस्ट, माहौल तनावपूर्ण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद (लखनऊ) मलिहाबाद में विधायक जयदेवी कौशल द्वारा बनवाए गए मलिहा पासी स्मृति द्वार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धीरे-धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। यह मामला अब केवल एक स्मृति द्वार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मुद्दा बन गया है। क्षेत्र में पासी समाज और अर्कवंशी समाज के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार, अर्कवंशी समाज के कुछ लोगों का दावा है कि मलिहा राजा पासी समाज से नहीं बल्कि अर्कवंशी समुदाय से संबंधित थे। उनका कहना है कि स्मृति द्वार का नामकरण और इससे जुड़ी पहचान गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है। वहीं, पासी समाज के लोगों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे अपने समाज के इतिहास और सम्मान पर सीधा हमला बताया है। पासी समाज का कहना है कि मलिहा पासी उनके समाज के गौरव हैं और उनके नाम पर बने स्मृति द्वार से किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर कुछ फेसबुक अकाउंट्स– 'क्षत्रिय एकता भारत' और 'Nirala Desh Bharat '– से लगातार भड़काऊ पोस्ट और वीडियो वायरल होने लगे। इन पोस्ट्स में कथित तौर पर स्मृति द्वार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी जा रही है, जिससे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की पोस्ट समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही हैं और इससे कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है।

सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मलिहाबाद के माहौल को जानबूझकर खराब करने और स्मृति द्वार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। क्षेत्र के कई जिम्मेदार नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस पूरे प्रकरण पर सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि स्मृति द्वार को हटाने या उससे छेड़छाड़ करने की कोई भी कोशिश की गई, तो पासी समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्मृति द्वार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

वहीं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शुभम पंडित का समर्थन पासी समाज को लगातार मिलता दिख रहा। वहीं सुहेलदेव आर्मी मलिहाबाद के प्रचारक अजीत पासी ने भी इसपर प्रशासन से नाराज़गी जताते हुए भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कारवाही कि मांग की है वहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इस पूरे मामले में सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सत्तापक्ष के नेता इसे कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भड़काया गया विवाद बता रहे हैं।

फिलहाल, मलिहाबाद का माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। आम नागरिकों में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री सामने आ रही है और दोनों समुदायों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है, उसे देखते हुए प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि वह इस विवाद को किस तरह शांतिपूर्वक सुलझाता है।

यूपी के ऊर्जा निगमों में भारी आक्रोशः 7 मई को प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार का ऐलान, जिलों में गूँजा 'सत्याग्रह'

● ...आउटसोर्स निगम में शामिल करने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा ; समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी जिलों में संविदा कर्मियों ने 'सत्याग्रह' कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा को दी गई उस पूर्व नोटिस के संदर्भ में किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा नवगठित 'आउटसोर्स निगम' में ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित करने की पुरजोर मांग की है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि 7 मई 2026 तक उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था ठप करते हुए कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

विधानसभा में की गई घोषणाओं पर प्रबंधन की बेरुखी

महासंघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ मजदूर नेता आर.एस. राय ने इस मौके पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल से यह घोषणा की थी कि प्रदेश के संविदा कर्मियों के बीच से बिचौलियों (ठेकेदारों) को हटाया जाएगा, उन्हें विभाग द्वारा सीधे वेतन का भुगतान होगा, मानदेय में वृद्धि की जाएगी और ईपीएफ का भुगतान भी सीधे विभाग सुनिश्चित करेगा। राय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की इस स्पष्ट मंशा के बावजूद पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन ऊर्जा निगम के संविदा कर्मचारियों को प्रस्तावित आउटसोर्स निगम से बाहर रखना चाहता है, जो न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है बल्कि हजारों कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय भी है।

शोषण और छंटनी के विरुद्ध निर्णायक जंग

महासंघ के प्रदेश प्रभारी पुनीत राय ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए कहा कि

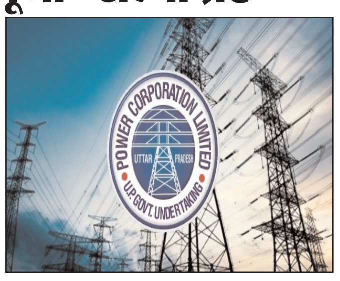

वर्तमान में संविदा कर्मी ठेकेदारों के शोषण और प्रतिदिन होने वाली अवैध छंटनी से त्रस्त हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और बिचौलिया प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए इन्हें आउटसोर्स निगम के दायरे में लाना अनिवार्य हो गया है। वहीं, विद्युत मज़दूर संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं महासंघ के मीडिया प्रभारी विमल चंद्र पाण्डेय ने सरकार और प्रबंधन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि 7 मई का कार्य बहिष्कार महज एक शुरुआत है। यदि इसके बाद भी संविदा कर्मियों को न्याय नहीं मिला और उनकी जायज मांगों को अनसुना किया गया, तो प्रदेश भर के ऊर्जा कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

सनकी युवक ने महिलाओं को दौड़ा- दौड़ा कर पीटा

● बोतल और डंडे से हमलाकर किया लहूलुहान

● दो की हालत गंभीर जिला अस्पताल रेफर

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के चमनगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 2 में सोमवार की देर रात करीब साढ़े दस बजे अचानक हड़कंप मच गया। एक अज्ञात युवक ने महिलाओं समेत कई लोगों पर हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए। दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में दो महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मोहल्ला निवासी माया देवी ने बताया कि वह घर के बाहर टहल रही थीं। जैसे ही अंदर जाने लगीं पीछे से आए युवक ने कांच की शीशी से सिर पर वार कर दिया। इसके बाद बबूल की कांटेदार लकड़ी से हमला किया। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं। वहीं मोहल्ले की ही गीता देवी जो दिव्यांग हैं ने बताया कि वह दरवाजे पर बैठी थीं। तभी युवक दौड़ता हुआ आया और उनका गला दबाकर जमीन पर पटक दिया। आरोपी ने साकेत नगर की निर्मला पर भी हमला किया। बचाने आए उसके बेटे निक्कू को भी डंडे से पीट दिया। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। कई लोग हाथों में डंडे लेकर सतर्क हो गए। सीएचसी में तैनात डॉ. एसके सिंह ने बताया कि सभी घायलों का इलाज किया गया। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को जिला अस्पताल भेजा गया है। पीड़ितों के मुताबिक हमला करने वाला युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने मोहल्ले गश्त बढ़ा दी है। इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवक को गिरफ्तार किया गया। वह मानसिक रूप से मानसिक बीमार लग रहा है। आरोपी को पड़कर उसे शांति भंग में पाबंद किया गया है।

हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य 21 सौ कलश यात्रा निकाली गई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जनपद बलरामपुर के मधपुर पकड़ी गांव में आयोजित दस दिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर मंगलवार को भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे से कथा स्थल से प्रारंभ हुई यह शोभायात्रा सेमरी, बेलवा और बिस्कोहर बस स्टाप होते हुए बूढ़ी राप्ती नदी के परसोहन घाट पर जा पहुंची। लगभग दो किलोमीटर लंबी इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने करीब सात किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। शोभायात्रा में 21 सौ कलश शामिल रहे, महिलाओं और बालिकाओं ने सिर पर कलश रखकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ कलश यात्रा में भाग लिया। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत और पुष्पवर्षा की गई, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और सुसज्जित रथों पर भगवान श्रीराम की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। इस दौरान

श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजक समिति के धनीराम प्रजापति ने बताया कि श्रीराम कथा का आयोजन 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें अवधपुरी से पधारे जगतगुरु श्री दिनेशाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर पंडित दुर्गेश शुक्ला, पूर्व विधायक शैलेन्द्र प्रताप सिंह , बिस्कोहर चेयर मैन अजय गुप्ता, फतेह बहादुर सिंह उर्फ पप्पू सिंह,नृपेन्द्र सिंह, राम नरेश पासवान, रक्षा राम प्रजापति, पंकज कुमार प्रजापति, धर्मेन्द्र शुक्ला, मनी राम प्रजापति, सियाराम प्रजापति, आदि लोग सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संकुल धरैंचा की अप्रैल माह की मासिक बैठक संपन्न

● .अपने कार्यों को समय पर तथा गुणवत्ता पूर्ण करना चाहिए तभी सफलता मिलेगीः-पूनम बाजपेई ए आर पी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर खैराबाद ब्लॉक के संकुल धरैंचा की अप्रैल माह की संकुल बैठक प्राथमिक विद्यालय धरैंचा में संपन्न हुई। बैठक मासिक एजेंडा के अनुसार संचालित की गई संकुल शिक्षकों द्वारा विभाग द्वारा प्राप्त एजेंडे के आधार पर गतिविधि कराई गई। बच्चों को सीखने की लय में लाने के लिए तथा विज्ञान किट के उपयोग और स्मार्ट क्लास, टैबलेट आईसीटी लैब ,के प्रभावी उपयोग, पोर्टल पर अपलोड समय सारणी के अनुसार कक्षाएं व गतिविधियां, इको क्लब, मौखिक भाषा विकास संबंधी खेल गतिविधियों आदि पर चर्चा की गई विद्यालयों के सर्वोत्तम एकेडमिक अभ्यास पर चर्चा की गई। संकुल बैठक में संकुल शिक्षक हसन जमाल रिज़वी ने विस्तार से बताया,बैठक में उपस्थित शिक्षकों के मध्य एक एक विंदु पर चर्चा की और सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करने का तरीका भी बताया। संकुल शिक्षक एजाज़ अहमद ने कहा कि हम सब साथी शिक्षक टीम भावना से कार्य करेंगे तो प्रगति होगी जबकि संकुल शिक्षक हसन जमाल एवं मुदित पाण्डेय ने कहा किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसे साझा करिए उसका तुरंत निदान किया जाएगा जबकि संकुल शिक्षक काजिम हुसैन ने तमाम बिंदुओं को अच्छे से समझाते हुए चर्चा की। ए आर पी अंग्रेज़ी भाषा पूनम बाजपेई ने सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि

अपने अपने विद्यालयों में शिक्षक डायरी अवश्य बनाएं और नियमित उसी के अनुसार कार्य करें जो भी कार्य करें पूरी तरह गुणवत्ता पूर्ण ढंग से करें तथा अपने कार्यो को सबसे पहले पूरा किया करें तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं निपुण आंकलन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शत प्रतिशत आवश्यक रूप से करवाना आवश्यक है क्योंकि यह जिला अधिकारी महोदय की प्रथम वरीयता में एक है।बैठक का शुभारंभ ए आर पी पूनम बाजपेई,अनीता ,मुदित पांडेय और शशी शुक्ला के द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके किया गया। बैठक में संकुल धरैंचा के 108 शिक्षकों के सापेक्ष 26 शिक्षक मौजूद थे। संकुल शिक्षक हसन जमाल रिज़वी,मुदित पाण्डेय एजाज़ अहमद तथा काज़िम हुसैन के द्वारा बैठक का डी सी एफ भरा गया जबकि संकुल शिक्षक फ़ैजुल हसन का तकनीकी समस्या के कारण भरा नहीं जा सका।संकुल के समस्त विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राथमिक विद्यालय धरैंचा के प्रभारी प्रधानाध्यापक भानु प्रताप और समस्त स्टाफ को व्यवस्थित बैठक और जलपान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया । बैठक का संचालन संकुल शिक्षक काज़िम हुसैन ने किया। बैठक के अंत में प्रभारी प्रधानाध्यापक भानु प्रताप तथा पूर्व प्रभारी नसरीन ने आभार व्यक्त किया।

संक्षिप्त खबरें

गर्मी से हर कोई परेशान, शीतल पेय की बढ़ी मांग

सिद्धार्थनगर। इन दिनों गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम के बदलते मिजाज से शीतल पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ना शुरू हो गई है। चौराहों पर शीतल पेय की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सुबह से ही धूप तेज रहने लगी और दोपहर होते-होते गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा। बाजारों और मुख्य मार्गों पर दोपहर के समय लोगों की आवाजाही भी कम नजर आई। तेज धूप के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। गर्मी बढ़ने के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ने लगी है। खेतों में सब्जियों को बचाने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। नलकूप और पंपसेट के सहारे किसान खेतों में पानी पहुंचाने के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। मौसम में यदि मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है।

मछली मंडी हटाने की मांग

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार कस्बा के बीचों बीच में मछली मंडी स्थापित रहने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कस्बा के रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर स्थित रेलवे की पुराने मॉल गोदाम के खाली पड़ी जमीन पर मछली मंडी स्थित है। मछली मंडी में साफ सफाई न रहने से काफी गंदगी रहती है इससे बदबू भी फैल रहा है। इससे हर कोई परेशान है। कस्बा के पवन मिश्र, राजकुमार, अभिषेक, राम उजागिर आदि ने प्रशासन से मछली मंडी कही अन्यत्र स्थापित करने की मांग की है।

एसआरएच बनाम डीसीः अभिषेक शर्मा की दिल्ली के सामने दबंगई, नौवां शतक ठोक तीन पूर्व कप्तानों के बराबर पहुंचे

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत उसकी तूफानी बल्लेबाजी है। इस टीम में अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज है जो अगर चल जाए तो गेंदबाज कांपते हैं। आईपीएल में अभिषेक निरंतर नहीं हैं, लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की है और शतकीय पारी खेली है। इसी के साथ उन्होंने खास लिस्ट में नाम लिखवा दिया। सिर्फ अभिषेक ही नहीं आज ट्रेविस हेड का बल्ला भी चला और इन दोनों ने मिलकर सनराइजर्स को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर 97 रन जोड़े और इसी के साथ बड़े स्कोर की नींव भी रख दी।

अभिषेक ने इस मैच में शतक ठोका। इससे पहले उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 74 रनों की पारी खेली थी। सनराजर्स के लिए ये मैच काफी अहम है और ऐसे में उसे अभिषेक से काफी उम्मीद थी। इस युवा बल्लेबाज ने टीम को निराश नहीं किया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। अभिषेक ने 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।नौवें ओवर फेंकने आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर दो रन लिए और अपना अर्धशतक पूर किया। यहां से अभिषेक ने अपने तूफानी अंदाज में और इजाफा किया। वह दिल्ली के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक ठोका। दिल्ली के पास अभिषेक को शतक से पहले आउट करने का मौका था, लेकिन जब वह 86 रनों पर थे तब नटराजन की गेंद पर नीतीश राणा ने कैच छोड़ दिया। अभिषेक ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का मार अपना शतक पूरा किया। इसके लिए अभिषेक ने 47 गेंदें लीं। ये अभिषेक के टी20 करियर का नौवां शतक है।

इस लिस्ट में पहुंचे अभिषेक

अभिषेक यहीं नहीं रुके। 59 रनों का मुकाम छूते ही वह एक खास लिस्ट में शामिल हो गए। जैसे ही अभिषेक ने अपना 59वां रन पूरा किया वह आईपीएल में एक टीम के लिए 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, भारत के शिखर धवन और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन शामिल हैं। ये तीनों ही इस फ्रेंचाइजी के कप्तान रह चुके हैं।

खोल दो नहीं तो...हॉर्मुज में चीन की एंट्री, ईरान को दिया सख्त आदेश!

● शी ने कहा कि चीन क्षेत्रीय देशों का समर्थन करता है कि वे परस्पर अच्छे पड़ोसी होने, विकास, सुरक्षा और सहयोग के आधार पर अपना भविष्य स्वयं अपने हाथ में रखें, तथा क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिमी एशिया का तनाव अभी निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर ईरान हॉर्मुज में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में एक नई एंट्री चीन की हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की है। इस चर्चा के दौरान ईरान और होर्मुज स्टेट की स्थिति पर विस्तार से बात हुई है। दरअसल, होर्मुद के बंद रहने से वैश्विक स्तर पर खासकर एशिया में ऊर्जा संकट गहरा गया है। चीन ईरानी तेल का प्रमुख आयातक है। अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के लंबे समय तक चलने से चिंतित है।

शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन क्षेत्रिय देशों को सदभावना, विकास और सहयोग के आधार पर एक साझा भविष्य बनाने के लिए समर्थन देता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य आवागमन जारी रहना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने और उसके बाद मौजूदा संघर्ष में अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर चीनी नेता का यह पहला बयान है। जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया भर में, विशेष रूप से एशिया में, ऊर्जा की भारी कमी हो गई है, और चीन, जो ईरानी तेल का एक प्रमुख आयातक है, अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के लंबे समय तक चलने को लेकर तेजी से चिंतित है।

शी ने कहा कि चीन क्षेत्रीय देशों का समर्थन करता है कि वे परस्पर अच्छे पड़ोसी होने, विकास, सुरक्षा और सहयोग के आधार पर अपना भविष्य स्वयं अपने हाथ में रखें, तथा क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें। उनकी यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी क्योंकि चीन ने पश्चिम एशिया में एक प्रमुख राजनयिक सफलता' हासिल की, जिसके तहत मार्च 2023 में कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान और सऊदी अरब को एक साथ लाया गया।

परिणामस्वरूप, दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल कर लिए। अमेरिका-ईरान संघर्ष ने लेकिन सब कुछ बदल दिया है, ईरान ने सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय देशों पर हमला करने के अलावा, उसके खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुकाबला करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। इसके अलावा, चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नौसेना द्वारा चीन से ईरान के बंदरगाह की ओर जा रहे उस मालवाहक जहाज पर गोलीबारी करने पर चिंता व्यक्त की है, जिसने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन किया था।

कटरीना की 'जिगरी यार' ने किया था आलिया भट्ट को सरेआम ट्रोल, अब दे डाली सफाई

नई दिल्ली। एक लाइव अवॉर्ड शो होस्ट करने के बाद आलिया भट्ट ट्रोलिंग और चर्चाओं का केंद्र बन गईं। इस आलोचना के बीच, एक्टर और होस्ट मिनी माथुर का एक कमेंट वायरल हो गया, जिसे कई लोगों ने आलिया भट्ट की होस्टिंग पर एक तंज माना। एक कंटेंट क्रिएटर की इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिनी के कमेंट के बाद यह बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद, मिनी ने अब आलिया पर तंज कसने के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, वह थी मिनी माथुर का उस इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पर किया गया कमेंट। मिनी ने एक सीधा-सादा, लेकिन असरदार कमेंट किया, जिसमें लिखा था, 'धन्यवाद। आखिरकार किसी ने तो यह बात कही'। उन्होंने आगे कहा, 'यह उनकी मुख्य काबिलियत नहीं है, तो फिर उनसे ऐसी उम्मीदें क्यों? यह तो ऐसा है जैसे किसी होस्ट से बंदूक की नोक पर एक्टिंग करने को कहा जाए। मैंने तो बस इसी बात पर कमेंट किया था'। जब उनसे पूछा गया कि क्या आलिया के साथ उनकी कोई कथित अनबन है, तो मिनी ने कहा, 'यह सब बकवास है। मैं आलिया को बहुत पसंद करती हूं। इसके अलावा मैंने तो वह शो देखा भी नहीं है जिसके बारे में ये लोग इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं'।

एस के चौबे के नेतृत्व में सामूहिक विवाह समारोह में पांच कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। एक कहावत आप सुने होंगे कि कर बहियां बल आपनी छोड़ पराई आस इस कहावत को सत्य साबित करते हुए कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहने वाले एस के चौबे जो पटेल नगर विधान सभा दिल्ली से संबंध रखते है ने राजनीतिक दलों से अपने सब संबंध खत्म करते हुए अपने साथियों संग टीम फाटक संघर्ष समिति के नाम से संगठन बनाकर अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को आज से लगभग 10 वर्ष पहले से करने लगे और कार्य बड़े पैमाने पर करने लगे जिसका परिणाम हुआ कि सभी राजनीतिक दल आज चौबे जी के कद के सामने बौनी नजर आने लगी। क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कभी भी चौबे जी से मदद मांगने में परहेज नहीं है और जनता का फोन आधी रात को चौबे जी उठाते है ऐसा जनता का कहना है। विगत वर्ष दो कन्याओं का विवाह सामूहिक समारोह के माध्यम से करवाए थे और इस वर्ष दिनांक 20 अप्रैल 2026 को पांच कन्याओं की शादी फिर से करके सच्चे समाज सेवक का परिचय चौबे जी द्वारा दिया गया। चौबे जी इस पवित्र कार्य का श्रेय अपने सभी साथियों और क्षेत्र की जनता को दिए। जब हमारे पत्रकार द्वारा पूछा गया कि आगामी वर्षों में भी क्या इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे तो इसके जवाब में चौबेजी बोले कि ऐसे आयोजन हर वर्ष होंगे जिससे हमारी जनता को राहत मिलती रहे।

समाज की सेवा करना तो सब चाहते है लेकिन सेवा में खरे उतरना सबके बस की बात नहीं है।एस के चौबे पेशे से तो इंजीनियर है लेकिन समाज निर्माण की भी भूमिका निभाने की काबिलियत रखते है ऐसा जनता का कहना है। जहां हर उभरते हुए चेहरे के प्रतिद्वंदी अधिकतर देखे जाते है वही चौबे जी के प्रतिद्वंदी कोई नहीं है ऐसा समाज देख रहा है।

पांचों कन्याओं की शादी बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुई जिसमें गिफ्ट के तौर पर बेड बिस्तर सहित, टेबल, 4 कुर्सी, सिलाई मशीन, टीवी, मिक्सर, जूसर, केटल, सूटकेश, 11 साड़ी, लड़की लड़के को घड़ी, 51 वर्तन का सेट, डिनर सेट, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, प्रेस, टब, मिठाई, चटाई, मैटी, श्रृंगार का सामान श्रृंगार दानी के साथ, लेडीज पर्स, स्टील का ड्रम, सोने की नथिया और भी बहुत उपहार देकर कन्याओं की बिदाई भी की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं स्थापित हो सकी भगवान परशुराम की मूर्ती-जीतेन्द्र प्रसाद द्विवेदी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हरदोई (उत्तर प्रदेश)– प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिन्दू साम्राज्य एवं वरिष्ठ समाजसेवी शाहजहांपुर जितेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कुछ ब्राह्मण समाज के यूवा भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा 19 अप्रैल अक्षय तृतीया को को ग्राम रामपुर थाना बघौली जिला हरदोई में स्थापित करना चाहते थे भगवान परशुराम जी की पांच फिट की भव्य प्रतिमा कुशल कारीगरों के द्वारा शाहजहांपुर में तैयार हुई ये प्रतिमा हुई मूर्ती स्थापना भण्डारा एवं भोभा यात्रा के लिए बघौली थाना प्रभारी से मुलाक़ात की गरी एस एच ओ बघौली ब्रजेश कुमार मिश्रा ने कहा इस कार्यक्रम के लिए उपजिलाधिकारी से परमीशन दे लीजिए दिनांक 6/4/26 को अशोक कुमार मिश्रा जिनकी निजी भूमि पर मूर्ती की स्थापना होनी थी उनके द्वारा भूमि के खतौनी एवं ग्राम प्रधान के शपथ पत्र संलग्न करके आवेदन दिया गया जब मूर्ती तैयार करवाकर दिनांक 17/4/26 को चिन्हित भूमि पर पहुंची उसी समय थाना बघौली से पुलिस पहुंची मूर्ती को स्थापित करने से ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी परमीशन कैंसिल हो गयी दिनांक 18/4/26 को मूर्ती स्थापना के लिए पूरे दिन प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे किसी ने नहीं सुना 18 शाम को एस एच ओ बघौली फोर्स सहित मूर्ती उठाकर थाने ले जाने के लिए आ गये ग्रामीणो के समझाने से मूर्ती को वहां से उठवा कर अशोक कुमार मिश्रा के घर पर रखवा कर वहीं पुलिस बल के साथ डेरा डाल दिया मूर्ती स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों एवं पुलिस प्रशासन के बीच कई राउंड बार्ता हुई लेकिन हर वार विफल रही।

मूर्ती स्थापना को लेकर ग्रामीण एवं ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी के आवास पर उनसे मिले मंत्री जी ने एस डी एम से फोन से बात करके ग्रामीणों से कहा जाओ मूर्ती स्थापित करो जाकर जब ग्रामीण गांव पहुंचकर मूर्ती स्थापना के लिए चले तभी पुलिस ने रोक दिया एस एस एच ओ ने कहा एस डी एम से बात करवा दीजिए ग्रामीणों ने बहुत कोशिश के बाद एस डी एम और मंत्री जी ने फोन रिसीव नहीं किया शाहजहांपुर से पहुंचे समाज सेवी जितेन्द्र प्रसाद द्विवेदी ने एस एच ओ बघौली से बात की तो एस एच ओ ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही मूर्ती स्थापना की परमीशन प्रशासन द्वारा करवा कर मूर्ती स्थापित एवं शोभायात्रा मैं करवाऊंगा समाजसेवी जितेन्द्र प्रसाद द्विवेदी के समझाने पर ग्रामीण मान गये एवं ज़िद छोड़कर भगवान श्री परशुराम जी की पूजा कर भण्डारा का शुभारम्भ किया गया ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन पर किसका दबाव था कि अपनी निजी भूमि जिस पर पहले से देव स्थान है उस पर मूर्ती स्थापित नहीं होने दी गयी जब कि केंद्र एवं राज्य में सनातनी सरकार है सनातनी सरकार में सनातन धर्म अब मज़ाक बनकर रह गया है।

बलिया में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज, 38 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

बलिया में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर करीब 38 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सभी परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक मौजूद रहे। अधिकारियों ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया। परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए 260 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना पहचान पत्र के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी को अनिवार्य रूप से आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र व्यवस्थापकों को साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खिड़कियों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 23 अप्रैल को एक और बैठक कर अंतिम तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले शिक्षकों को ही परीक्षा कार्य में लगाया जाए। परीक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 05498-220830 और 05498-220235 जारी किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है।

श्रीभूमि जिले के कृष्णनगर आदर्श गांव में बिजली संकट गहराया, केबल लाइन की जोरदार मांग

● विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुल्लभछड़ा के निकट स्थित मॉडल विलेज कृष्णनगर के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बिजली समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बार-बार आवेदन करने के बावजूद Assam Power Distribution Company Limited (ASEB) के दुल्लभछड़ा सब-डिवीजन द्वारा अब तक क्षेत्र में केबल लाइन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में पेड़-पौधे और बांस की अधिकता के कारण खुले तारों के बजाय केबल लाइन बिछाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

आरोप के अनुसार, पिछले वर्ष से इस मुद्दे को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे ग्रामीण खुद को बेहद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी बीच, क्षेत्र में बार-बार हो रही लोडशेडिंग को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाती है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खासकर मौसम में बदलाव के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार घंटों तक बिजली गुल रहती है, जो ग्रामीण जीवन के लिए बड़ी समस्या बन गई है।

एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'हम नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं, फिर भी हमें उचित सेवा नहीं मिल रही है। यह उपभोक्ताओं के प्रति घोर लापरवाही है।' ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्था और जिम्मेदारी की कमी का परिणाम है। उन्होंने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों–हैलाकांडी डिवीजन के तरू बदरपुर सर्कल के ष्ठत्तरूसहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप कर केबल लाइन स्थापित करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

सी एसके फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज, आयुष म्हात्रे के झटके के बीच एमएस धोनी धांसू वापसी को तैयार

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स को मंगलवार को एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज मिली। दोपहर में फ्रेंचाइजी ने बताया कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आयुष म्हात्रे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। शाम होते-होते फ्रेंचाइजी ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का अभ्यास करते हुए एक वीडियो शेयर किया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि धोनी अब फिट हो गए हैं और वह आने वाले मुकाबलों में वापसी कर सकते हैं।

विकेट के पीछे मुस्तैद

चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्स पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि धोनी विकेट के पीछे मुस्तैद हैं। बल्लेबाज ने आगे बढ़कर शॉट लगाने का प्रयास किया और गेंद मिस हो जाती है। विकेट के पीछे धोनी कोई गलती नहीं करते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि धोनी की जल्द ही वापसी होने वाली है।

पहले 6 मैच नहीं खेले धोनी

महेंद्र सिंह धोनी पिंडली की चोट (calf injury) से जूझ रहे हैं। इस कारण वह 19वें

सीजन के पहले 6 मैच नहीं खेले हैं। इस दौरान फ्रेंचाइजी ने सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत दर्ज की है। चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद से उन्हें हार मिली है। आने वाले मुकाबलों की बात करें तो 23 अप्रैल को चेन्नई का सामना मुंबई इंडियंस से और 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से होगा।

धोनी के प्रदर्शन पर नजर– एमएस धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से रहे हैं। उनके नेतृत्व में चेन्नई ने 5 खिताब अपने नाम किए थे। धोनी ने लीग में अब तक 278 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 39 की औसत और 137 की स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए हैं।, आईपीएल में वह 24 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 84 रन है।

दिल्ली के बुराड़ी में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। यहां आरोपित कलियुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। आरोपित नशे का आदि है। बुराड़ी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपनी पोती और बेटे के साथ बुराड़ी इलाके में रहती हैं। वह घरों में घरेलू काम कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। वहीं, उसका 36 वर्षीय बेटा लंबे समय से नशे का आदी है और कोई काम-धंधा नहीं करता। वह आए दिन घर में झगड़ा और मारपीट करता था। घटना की शुरुआत शुक्रवार को हुई जब आरोपी ने अपनी 16 साल की बेटी को पीट दिया। पिता के रोजाना के कलेश से तंग आकर बेटी अपनी बुआ के घर चली गई। शनिवार रात जब घर में बुजुर्ग मां अकेली थी। तभी आरोपी बेटा नशे में धुत होकर पहुंचा। जब उसकी मां ने उसे खाना खाने को कहा तो वह भड़क गया और अपनी मां को ही बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।तड़के जब वह सो गया तो किसी तरह मां ने खुद को रस्सियों से खोला और थाने में जाकर शिकायत की।

असम विश्वविद्यालय सिलचर में 'आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और उससे आगे' विषय पर 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः असम विश्वविद्यालय, सिलचर (AUS) के भौतिकी विभाग द्वारा पुणे स्थित इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) तथा IUCAA सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ICARD) के सहयोग से आज 'आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और उससे आगे' विषय पर पाँच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला गत 20 से 24 अप्रैल 2026 तक भौतिकी विभाग के मेघनाद साहा कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान और उन्नत शोध-स्तरीय समझ के बीच की खाई को कम करना है, जिससे छात्रों एवं शोधार्थियों को आधुनिक भौतिकी की गहन अवधारणाओं की बेहतर समझ मिल सके। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भौतिकी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. अशोक कुमार सेन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. पैट्रिक दासगुप्ता उपस्थित रहे। मंच पर विभागाध्यक्ष प्रो. हिमाद्रि शेखर दास, कार्यशाला समन्वयक एवं स्कूल ऑफ

फिजिकल साइंसेज के डीन प्रो. अत्रि देशमुख्य, तथा द्धष्ट समन्वयक डॉ. अप्रतिम गांगुली सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त आईएसआई कोलकाता की डॉ. भास्वती मंडल एवं आईआईटी गुवाहाटी के डॉ. सयान चक्रवर्ती सहित अन्य विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतीकात्मक पौधारोपण के साथ की गई। इसके पश्चात उद्घाटन व्याख्यान में प्रो. अत्रि देशमुख्य ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन विशेष रूप से उन विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें सामान्य सापेक्षता जैसे जटिल विषयों पर व्यवस्थित प्रशिक्षण कम मिलता है।

डॉ. अप्रतिम गांगुली ने द्धष्ट की शैक्षणिक भूमिका और ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रो. हिमाद्रि शेखर दास ने विभाग की शैक्षणिक उपलब्धियों और निरंतर आयोजित होने वाली अकादमिक गतिविधियों का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि प्रो. पैट्रिक दासगुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भी गणितीय समस्याओं को स्वयं हल करने की प्रक्रिया शोधकर्ताओं के बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रतिभागियों की भागीदारी इस कार्यशाला में कुल 61 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें पीएचडी शोधार्थी, एम. एससी. छात्र तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। प्रतिभागी असम एवं त्रिपुरा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए हैं। उद्घाटन सत्र का संचालन सुश्री संचाली नाथ मजूमदार द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

ट्रेन संख्या 15888 गुवाहाटी-बदरपुर विस्टाडोम एक्सप्रेस को दुल्लभछड़ा तक विस्तार की मांग तेज

● प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का ध्यान आकर्षित, सोनबील को केंद्र बनाकर पर्यटन विकास की अपील।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः पर्यटन विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार रेलवे के माध्यम से यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं शुरू कर रही है। विशेष रूप से विस्टाडोम कोच से युक्त ट्रेनों के जरिए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है, जिस पर सरकार द्वारा भारी खर्च भी किया गया है। इसी संदर्भ में श्रीभूमि (करीमगंज) जिले के दुल्लभछड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने ट्रेन संख्या 15888 गुवाहाटी-बदरपुर विस्टाडोम एक्सप्रेस को दुल्लभछड़ा तक विस्तारित करने की मांग तेज कर दी है। वर्तमान में यह ट्रेन गुवाहाटी से बदरपुर जंक्शन तक सप्ताह में दो दिन बुधवार और शनिवार चलती है। लगभग 340-341 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे करीब 7 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। रास्ते में Maibang, New Haflong और Jatinga सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इसका ठहराव है। विस्टाडोम कोच होने के कारण यात्री पहाड़ी प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस ट्रेन को दुल्लभछड़ा तक बढ़ाया जाए और फाकुआ रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए, तो सोनबील के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। विशेष रूप से सोनबील, जो असम का सबसे बड़ा तथा एशिया के प्रमुख मौसमी आर्द्रभूमियों में से एक है, पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सकता है। लोगों का मानना है कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दुल्लभछड़ा और सोनबील क्षेत्र को यदि बेहतर रेल संपर्क मिल जाए, तो यह एक ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, होटल व्यवसाय और छोटे व्यापारों को भी बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र के लोगों ने कहा,

'विस्टाडोम ट्रेन हमारे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर इसे दुल्लभछड़ा तक बढ़ाया जाता है, तो पर्यटन और आवागमन दोनों में सुधार होगा।' इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से जोरदार अपील की है कि गुवाहाटी-बदरपुर विस्टाडोम एक्सप्रेस को दुल्लभछड़ा तक विस्तारित किया जाए और सोनबील के पास स्थित फाकुआ स्टेशन पर सप्ताह दो दिन विस्तार की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि इस पहल से बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन व आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।